an>

title: Need to release Central Government's share under J.N.N.U.R.M. scheme.

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : महोदय, जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत नगर विकास की एक योजना है और इसकी ही एक उपयोजना यू.आई.जी. है। जो उत्तर प्रदेश के सात नगरों लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ तथा मथुरा में चल रही है। इस योजना का 10 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार ने अब तक रिलीज नहीं किया है। उसके रिलीज न होने से इन तमाम योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए निगरानी समिति हुई। निगरानी समिति ने भी कहा कि काम ठीक हो रहा है। इसके बाद तारीख दी गई लेकिन तारीख देने के बावजूद भी पैसा आज तक नहीं मिला। मेरा आग्रह है कि इसका पैसा तुरंत रिलीज़ किया जाए। इसके साथ-साथ मेरे दो सुझाव हैं।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के तहत सृजित परिसम्पतियों के अनुरक्षण की लागत को भी परियोजना लागत में शामिल कर लिया जाए तथा तदनुसार केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि जारी की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार से निधियों की किस्तों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण परियोजना की लागत बढ़ रही है। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, राज्य सरकार को अपने संसाधनों से ही बढ़ी हुई लागत को सहन करना होता है। अतः बढ़ी हुई लागत को केन्द्र तथा राज्य सरकार को आनुपातिक आधार पर वहन करना चाहिए।

परियोजनाओं के अंतर्गत जरूरी भूमि के अधिग्रहण की लागत, परियोजना लागत में शामिल कर ली जानी चाहिए तथा इसे समानुपातिक आधार पर वहन करना चाहिए। जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम की शहरी परिवहन उपयोजना के अंतर्गत आवश्यक अवसंरचना अर्थात् बस डिपो, कार्यशाला, जंक्शन आदि के विकास की लागत को केन्द्रीय सरकार द्वारा वित पोषित किया जाना चाहिए।